

प्रेस रिलीज़

20 जुलाई 2021
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट की इजरायली स्पाइवेयर के इस्तेमाल की न्यायिक जांच की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ एम ए सलाम ने अपने एक बयान में इजरायली स्पाइवेयर के इस्तेमाल की खबरों की न्यायिक जांच की मांग की है।

भारत में पेगासस के इस्तेमाल की खबरें हैरान करने वाली हैं। पेगासस जैसे प्रोडक्ट्स के द्वारा इजराइल मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और दुनिया भर की लोकतांत्रिक गतिविधियों और स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर कर रहा है। इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा तैयार किए गए स्पाइवेयर 'पेगासस' के बड़े खरीदारों में तथाकथित लोकतांत्रिक देश और तानाशाही सरकारें दोनों शामिल हैं, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपने नागरिकों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करने के लिए बदनाम हैं। एक तरफ कंपनी का यह दावा है कि इस प्रोडक्ट का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना है, लेकिन दूसरी ओर जुनूनी सरकारें इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं, सरकारी पदाधिकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्राइवैसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए प्राकृतिक है। भारत में पेगासस के निशाने पर जिन लोगों के नाम हैं वह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन शोषण के मामले को देखने वाले सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का नाम शामिल है। अब तक जो नाम सामने आए हैं वे आतंकवादी या देश के लिए खतरा नहीं है। अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह पता लगाए कि देश में कौन भारत के जानी-मानी हस्तियों को हैक करने का प्रयास कर रहा है और वह उनकी जासूसी के लिए लाखों डॉलर देने के लिए तैयार है।

जिन डिवाइसों को निशाना बनाया गया है सरकार की ओर से उनकी फॉरेंसिक जांच न कराने की चाहत बल्कि इसके बजाय नागरिकों की इस बड़े पैमाने पर जासूसी को सही ठहराने का रुझान शक पैदा करता है। भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह एनएसओ की खरीदार है या नहीं।

अगर भारत सरकार इस जासूसी के पीछे नहीं है तो वह अज्ञात ताकतों की ओर से इस प्रकार के गंभीर हमलों से नागरिकों की प्राइवैसी को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है। अगर इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और ज़्यादा गंभीर बन जाता है, जिसके बाद पहले से ज़्यादा चौकसी और सक्रियता बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यह चीज़ भी नहीं दिख रही है।

इसलिए पॉपुलर फ्रंट प्राइवैसी पर देश के इतिहास के सबसे खतरनाक और नापाक हमले के पीछे की ताकतों को बेनकाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करता है।

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली